सतर्कता

18
अध्याय

सतर्कता

1. कार्य

कोयला मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठनों अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी 8 सहायक कंपनियों; एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल); कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मुद्दों के अलावा मंत्रालय के सतर्कता प्रशासन की देखरेख करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मुद्दों का समन्वय करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों का निपटान केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 'शिकायत निपटान नीति' के अनुसार किया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए औचक जांचों, नियमित जांचों, गुणवत्ता जांचों, अनुवर्ती जांचों और सीटीई प्रकार की परीक्षाओं जैसे सक्रिय, निवारक और दंडात्मक तरीके से शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली (सीटीएस) का उपयोग करके प्रारंभ से निपटान तक कार्रवाई की जाती है।

सामान्यतः संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/कर्मचारियों और आम जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों की प्रकृति मुख्य रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, निविदाओं में अनियमितताओं, मुआवजे के संबंध में ४ष्टाचार आदि के संबंध में कोयला मंत्रालय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारियों / अधिकारियों के खिलाफ होती है।

2. संगठन संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में संयुक्त सचिव होते है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता विंग के अध्यक्ष प्रतिनियुक्ति आधार पर सीवीओ द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उपर्युक्त संगठनों के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मुद्दों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है और बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में, कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3. सतर्कता जागरूकता मनाया जाना

"सर्तकताः हमारी जिम्मेदारी" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27.10.2025 से 02.11.2025 तक मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालय में सत्यनिष्ठा शपथ, निबंध लेखन

प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया गया। सतर्कता मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी कंपनियों में इसी प्रकार के कार्यकलाप भी किए गए थे।

vities were also undertaken in all the companies to create awareness on vigilance issues.

4. समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों से संबंधित लंबित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सीवीओ के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। **सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान 04.03.2025 और 12.11.2025 को ऐसी दो बैठकें आयोजित की गई।**

5. 2025–26 के दौरान जारी किए गए प्रणालीगत सुधार उपाय

सभी संगठन अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, संवेदनशील से गैर–संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के चक्रानुक्रम स्थानांतरण आदि में सक्रिय भागीदार हैं। इसके अलावा, वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख प्रणाली सुधार सुझाव दिए गए: –

सीआईएल के प्रणालीगत सुधारात्मक उपाय

क. सीआईएल और सहायक कंपनियों के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सतर्कता प्रभाग (मुख्यालय) द्वारा शुरू की गई Mission_Brand_CIL/50 के बैनर तले अपनी सभी सहायक कंपनियों में अभिनव और प्रभावशाली सतर्कता पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। सतर्कता प्रभाग सीआईएल की पहल का मुख्य उद्देश्य कार्य वातावरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों में कार्यपालकों के स्थानांतरण और तैनाती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और एकरूपता बढ़ाने के लिए, सीआईएल प्रबंधन को निम्नलिखित प्रणालीगत सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया था:

1. **एक एकीकृत वेब–आधारित स्थानांतरण प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत:** कार्यकारी स्थानांतरण अनुरोधों की सभी श्रेणियों को संभालने के लिए एक समर्पित, केंद्रीकृत स्थानांतरण प्रबंधन पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए।
2. **परिभाषित समयसीमा के साथ मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी):** स्थानांतरण और तैनाती के लिए एक विस्तृत एसओपी जारी की जानी चाहिए और पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
3. **पारस्परिक और अनुरोध पर स्थानान्तरण की डिजिटल प्रोसेसिंग:** पारस्परिक स्थानांतरण और सामान्य अनुरोध पर स्थानांतरण को पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से पेपरलेस मोड में संसाधित किया जाना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करना, आपसी स्थानांतरण अनुरोधों का ऑटो–मिलान, वास्तविक समय रिक्ति मानचित्रण जैसी विशेषताएं शामिल हैं। स्थिति ट्रैकिंग एसएपी, ऑटो–जनरेटेड अनुमोदन/अस्वीकृति आदेश के साथ जुड़ी हुई है।
4. **मेडिकल ग्राउंड ट्रांसफर:** चिकित्सा मामलों में शामिल संवेदनशीलता और तात्कालिकता को देखते हुए, एक समर्पित मेडिकल ग्राउंड ट्रांसफर पोर्टल बनाया जा सकता है जिसमे चिकित्सा दस्तावेजों, नुस्खे, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट आदि के लिए अपलोड करने की सुविधा शामिल है। पैनल में शामिल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सत्यापन, की सुविधा शामिल है। वर्कफ़्लो में प्राथमिकता रूटिंग के साथ फास्ट–ट्रैक प्रोसेसिंग और उसके साथ एक नीति, ऐसे मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल आधार पर निपटान के लिए एक परिभाषित समय–सीमा।
5. **निगरानी, लेखापरीक्षा और एमआईएस:** दोनों पोर्टलों में लंबित पेंडेंसी, निपटान दर और समयसीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रबंधन के लिए एमआईएस डैशबोर्ड होने चाहिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी उपयोगकर्ता कार्यों के लिए डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स। जनशक्ति नियोजन और नीतिगत निर्णयों के लिए विश्लेषण।इन प्रणालीगत सुधारों को लागू करने से बढ़ी हुई पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करके, मानवीय हस्तक्षेप को कम करके और तेजी से प्रोसेसिंग को सक्षम करके समग्र स्थानांतरण और तैनाती तंत्र में काफी सुधार होगा जो सीधे बेहतर कर्मचारी संतुष्टि में योगदान देता है। सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो और रीयल–टाइम डेटा

एकीकरण के साथ, यह प्रणाली सभी संगठनात्मक स्तरों पर समान नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में बेहतर जनशक्ति नियोजन का समर्थन करेगी।कुल मिलाकर, ये उपाय विलंब को समाप्त करेंगे, अधिक एकरूपता लाएंगे और पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह अंतरण ढांचा स्थापित करेंगे।

ख. बिलों का पारित होना:

अंतिम बिल जमा करने के बाद विलंबित भुगतानों के निपटान में दक्षता में सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपाय प्रस्तावित किए गए थे:

1. विभाग के भीतर बिलों के आंतरिक (टेबल–टू–टेबल) मूवमेंट के लिए रिकॉर्ड कीपिंग को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है।

2. सभी बिलों को एक समान मानदंड के तहत संसाधित किया जाना चाहिए जैसे कि फर्स्ट इन–फर्स्ट–आउट (फीफो) विधि। इस प्रक्रिया से किसी भी विचलन की अनुमति केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही दी जा सकती है। ऐसे अपवादों की अनुमति देने के लिए, लगातार निर्णय लेने को सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए।

3. क) बिल प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

   ख) ईआरपी के माध्यम से बिल ट्रैकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बिलों की प्राप्ति और प्रोसेसिंग को संभालने और विक्रेताओं और कर्मचारियों को कागज रहित भुगतान को सक्षम करने के लिए, प्रबंधन को विक्रेता चालान प्रबंधन (वीआईएम) जैसे ईआरपी मॉड्यूल के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया था। सीआईएल प्रबंधन ने दिनांक 01.01.2025 से बिलों और विभिन्न दावों की प्रोसेसिंग के लिए एसएपी के माध्यम से डिजिटलीकरण के लिए एक एसओपी जारी की है।

एनएलसीआईएल के प्रणालीगत सुधार उपाय

क. ठेकेदार द्वारा छोड़े गए नामांकन कार्य:

'टीपीएस–II में टीपीएस–II बॉयलरों की दो मिलों में मिलों और पीएफ डक्ट्स ओवरहाल कार्य' के लिए तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नामांकन अनुबंध प्रदान किया गया था।हालांकि, ठेकेदार ने काम को बीच में ही छोड़ दिया, और यह देखा गया कि ठेकेदार की साख के पर्याप्त सत्यापन के बिना ठेका दिया गया था।इस मामले में, सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल ने नामांकन के आधार पर कार्य देने से पहले ठेकेदार की साख सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। नामांकन प्रस्तावों में ठेकेदारों की साख सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया था। फर्म को एक चेतावनी पत्र भी जारी किया गया था।

ख. निविदा शर्तों के बीच विचलन और कार्यों के लिए नोट अनुमोदन।

40.0 हेक्टेयर में 3 मीटर तक की मिट्टी को हटाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था – जिसमें 4 एलसीएम ऊपरी मिट्टी (1 मीटर गहराई) और 8 एलसीएम उपमृदा (2 मीटर गहराई) शामिल थी। हालांकि, निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से किसी भी परत के लिए खुदाई की गहराई को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। निष्पादन के दौरान, 1.43 एलसीएम ऊपरी मिट्टी और 10.11 एलसीएम उप–मिट्टी को हटा दिया गया, जबकि 2.86 एलसीएम उप–मिट्टी की स्वीकृत मात्रा थी। इसके परिणामस्वरूप 7.25 एलसीएम उप–मिट्टी को हटा दिया गया – जो प्रशासनिक रूप से अनुमोदित मात्रा से 253% अधिक है। वर्तमान मामले में, सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल ने प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।

ग. रिवर्स नीलामी (आरए) के लिए विक्रेताओं के उन्मूलन में एनईएटी और जीईएम पोर्टलों के बीच विसंगति।

सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एनईएटी में जीईएम आरए नीति अपनाने का सुझाव दिया।इसे एनएलसीआईएल के प्रचालनरत अनुबंध और खरीद नियमावली में शामिल किया जाएगा।

घ. ब्रांड का नाम और "प्रतिष्ठित मेक" को इंगित करने वाली निविदा शर्तें।

सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल ने भविष्य की निविदाओं में "प्रतिष्ठित निर्माण" जैसी व्यक्तिपरक या गैर–मानक शब्दावली से बचने की सिफारिश की/सुझाव दिया।

ड. रखरखाव संबंधी नौकरियों को प्रचालनात्मक नौकरियों के साथ श्रम आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

अनुबंध के रखरखाव कार्यों को प्रचालन भाग के साथ श्रम आपूर्ति अनुबंध के रूप में तैयार किया गया था। इसने किए गए रखरखाव कार्य को मापने और उसके अनुसार बिल बढ़ाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं ।सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल ने सिफारिश की कि रखरखाव निविदाओं को श्रम आपूर्ति अनुबंध के रूप में संरचित करने के बजाय जॉब कोड, मात्रा, इकाई दर और राशि को परिभाषित करने वाले आइटम दर अनुबंधों के रूप में जारी किया जाना चाहिए।

च. ईओटी क्रेन की लोड और स्थिरता की जांच।

निविदा दस्तावेजों में लोड परीक्षण और स्थिरता जांच के लिए लागू आईएस मानकों या एसओपी को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप असंगत निष्पादन और आवश्यकताओं की व्याख्या हुई। नतीजतन, दोनों क्रेनों के लिए लोड परीक्षण आईएस 3177 में निर्धारित अनिवार्य 125: अधिभार क्षमता से नीचे आयोजित किया गया था, और परीक्षण पद्धति मानक प्रक्रियाओं से विचलित हो गई, जिससे स्थिरता मूल्यांकन की विश्वसनीयता कम हो गई ।सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल ने आईएस मानकों के अनुरूप स्वीकार्य प्रक्रियाओं और सीमाओं (एसडब्ल्यूएल, गतिशील/स्थिर भार) को परिभाषित करने की सिफारिश की/सुझाव दिया। भविष्य के अनुबंधों में सिफारिशों को शामिल किया जाएगा।

छ. ऐश पोंड से लाल मिट्टी की चोरी।

ऐश पोंड के आधार से ताजी लाल मिट्टी की खुदाई देखी गई। तालाबों की भीतरी बांध की मिट्टी भी खुदाई की गई पाई गई। सतर्कता विभाग, एनएलसीआईएल की सिफारिश पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ऐश पोंड में सीआईएसएफ को तैनात किया गया है।

6. दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक शिकायतों, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति का विवरण

प्राप्त, निपटाए गए और लंबित शिकायतों तथा मामलों का विवरण (सामान्य/वीआईपी/पीआईडीपीआई/सीवीसी)

स्रोत	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटारा	शेष	आयुवार लंबित मामले (महीने)			
						<1	1.3	3.6	>6
सामान्य	47	436	483	458	25	10	7	7	1
वीआईपी	1	10	11	8	3	2	1	0	0
पीआईडीपीआई	3	12	15	8	7	0	3	3	1
सीवीसी (आईएंडआर औऔर एफआर)	4	9	13	7	6	2	4	0	0

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण – दीर्घ

स्रोत	अथ शेष	इस अवधि के दौरान आईओ को सौंपी गई जांच	कुल	आईओ से प्राप्त रिपोर्ट	आईओ के पास लंबित जांच	आयुवार लंबित मामले (महीने)			
						<6	6.12	12.18	>18
दीर्घ दंड मामले	1	0	1	1	0	0	0	0	0

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण - लघु

स्रोत	अथ शेष	इस अवधि के दौरान डीए द्वारा लघु शास्ति का आरोप पत्र	कुल	ऐसे मामले जिनमें डीए द्वारा अंतिम आदेश जारी किए गए हैं	शेष लंबित	आयुवार लंबित मामले (महीने)			
						<6	6.12	12.18	>18
लघु शास्ति के मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अभियोजन स्वीकृति का विवरण

अथ शेष	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल	दी गई मंजूरी	मंजूरी देने से इनकार कर दिया	शेष राशि लंबित
1	3	3	3	0	0